ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of the Press briefing — Held at 1615 Hours 11.08.2014

Shri Anand Sharma addressed the media today.

श्री आनन्द शर्मा ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शनिवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कहीं जो अपने आप में चौंकाने वाली हैं असत्य हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं। चुनाव प्रचार के दौरान यह अपेक्षा श्री नरेंद्र मोदी जी से की जा सकती थी कि वो ऐसी बात कहें जिससे लोग स्तब्ध हों या अपने विरोधियों को विशेषकर कांग्रेस पार्टी और यूपीए को कटघरे में खड़ा करें। प्रधानमंत्री का यह कथन कि उनकी सरकार ने एक मजबूत निर्णय लिया डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्दर जिससे इस देश के किसानों की रक्षा हुई, उनके हितों की और खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार है भारत का,उसको भी उन्होंने सुरक्षित किया।

मैं इस पर आपको बताना चाहता हूं, कल भी हमने एक वक्तव्य के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला है ताकि लोग गुमराह ना हों। यह कथन असत्य है, तथ्यों को नकारता है लोगों को गुमराह करता है। यह अपेक्षा की जाती है कि देश के प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी बात कहें तो उनका दल उनके दल, के नेता और उनके मंत्री उन्हें अर्न्तराष्ट्रीय मंच पर, संस्थाओं में भारत की क्या सोच रही है, भारत ने क्या स्टैंड लिया है, उसकी पूरी तरह से जानकारी थी। अगर देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने अनभिज्ञ पाया जाए, अज्ञान पाया जाए, तो भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है।

पहली चीज नरेंद्र मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं और भाजपा सरकार को कि खाद्य सुरक्षा देश का अपना अधिकार है, यह कभी किसी अर्न्तराष्ट्रीय करार में, चर्चा में, फोरम में, डब्ल्यू. टी. ओ में एजेन्डा पर नहीं रहा यह बुनियादी भूल और गलत बात है। दूसरी बात 1995 में डब्ल्यू.टी. ओ. का गठन हुआ था, 1998 से 2004 तक एनडीए भाजपा की सरकार इस देश में थी, वर्तमान में वित्त मंत्री जो उस समय एक मंत्रिय शिखर में कैनकुन में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे उन्होंने जो कहा था, अगर वही सोच मान ली जाती हमारे द्वारा तो इस देश का अहित होता,

किसान का नुकसान होता, देश के अधिकार की रक्षा ना रहती। वो एक calibrated approach. के लिए मान गए थे और आप उस समय के वक्तव्य मंत्रिय शिखर सम्मेलन की जो घोषणा है उसको आप पढ़ सकते हैं। 1995 से लेकर दिसंबर–2013 तक एक ज्वलंत विषय, हिन्दुस्तान के लिए चिंता का था, अन्य विकासशील देशों के लिए, वो कभी चर्चा में नहीं लाया गया। वो विषय खाद्य सुरक्षा का नहीं है वो विषय जो हम किसान से खरीदते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसका एक यूरगुए राउन्ड का एग्रीमेंट जो 1994 में दस्तखत हुए थे उसके तहत जो नियम बने उसको हमने गलत पाया। क्योंकि उसमें दस प्रतिशत की अनुमति है पर वो दस प्रतिशत की calculation जिसको de-minimus कहते हैं, वो एक External reference price कहा जाता है यूरगुए राउन्ड के एग्रीमेंट में जो 1986 से 1988 का था। 1995 से दिसंबर 2013 तक वो नहीं बदला गया उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जो बड़े देश थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इसको चर्चा में लाए, इसको एजेंडा पर लाए। 2013 में भारत ने मजबूर किया कि यह विषय एजेंडा पर लाया जाए पहली बार यह विषय एजेंडा पर आया यह विषय चर्चा में आया और जो दस समझौते हुए उसमें एक समझौता इस विषय पर था। भारत ने बाली के अन्दर यूरगुए राउन्ड के External reference price को नकार दिया, हमने कहा यह अस्वीकार है–21वीं सदी में चलिए। यह भारत के और अन्य प्रगतिशील देशों के खिलाफ है, यह न्योयोचित नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानते, यह एक वास्तविकता है। तब यह तय हुआ कि ग्यारहवें मंत्रिय शिखर सम्मेलन में एक स्थाई समाधान, जो बातचीत के जरिए होगा इस विषय पर लागू कर दिया जाएगा। अन्तरकाल में जब तक बातचीत के दौरान एक स्थाई समाधान लागू नहीं होता कोई भी राष्ट्र जो डब्ल्यू. टी. ओ. का सदस्य है, दूसरे राष्ट्र को युरगुए राउन्ड का Agreement on agriculture या de-minimus उसका उल्लंघन चुनौती नहीं दे सकता हम एक अपने अधिकार को सुरक्षित लेकर आए थे जो 1995 से भारत पर एक खतरा मंडरा रहा था वो बाली में समाप्त हुआ। अगर आप उसको पढ़ें, उसमें स्पष्ट है कि 11वीं मंत्रिय शिखर सम्मेलन तक निश्चित रूप से इसका समाधान होगा तब तक कोई चुनौती नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं जो भाजपा कहती है चार बरस का था। चार बरस के अन्दर

The wording by MC 11 - definitely negotiated permanent solution will be put in place and paragraph 2 of the same says that in the interim until a permanent solution is reached, no Member country shall challenge another Member country for the breach.

यह जो मोदी जी कहते हैं कि हम देश के हित को यानि खाद्य सुरक्षा के हित को बेचकर आए थे। मैंने पहले बताया कि खाद्य सुरक्षा तो हमने कभी चर्चा में आने नहीं दी।

The Food security has never been a part of the agenda. India never accepted it at WTO or any multilateral forums because this is the sovereign space and sovereign right. We

did expect the Prime Minister of India to be well informed and literate about these matters and not to make a statement which actually will shock the entire world about his lack of knowledge.

दूसरा विषय कि वो अधिकार को सुरक्षित करके लाए– हम प्राप्त करके लाए थे। जेनेवा में वो खो दिया गया। General Council collapse हुई है। यह बयान सरकार का कि सितंबर के बाद जाएंगे–सबको बुला लेंगे–जैसे पूरी दुनिया इनके दरवाजे पर खड़ी है। वो 160 देशों का फैसला था– 160 देशों के दस्तखत थे उसको बदला नहीं जा सकता जब तक अगला मंत्रिय शिखर सम्मेलन ना हो।

हमने आज इस विषय को संसद में उठाया। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते वो बाहर भाजपा की कार्यकारिणी में बोलते हैं–हमने यह मांग की थी हमने नियमों के निलम्बन का नोटिस दिया था ताकि इस पर चर्चा हो और देश के प्रधानमंत्री, मंत्री जो विद्धान हैं इन विषयों पर संसद में आकर बात करें। वो उसके लिए तैयार नहीं हैं वो अपने मंत्रियों को अपने आगे ढ़ाल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। बेहतर यह होगा कि वे स्वयं आकर बात करें। यह प्रश्न मंत्री के बयान का नहीं है यह प्रश्न प्रधानमंत्री की अज्ञानता का है, प्रधानमंत्री की गलत बयानी का है। प्रधानमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान का है, यह बुनियादी बातें हैं।

एक बात और हम देश को बताना चाहते हैं कि आज जो परिस्थिती है जो हम यह रक्षा कवच लेकर आए थे और स्थाई समाधान का वचन, वो आज उपलब्ध नहीं है। जब तक सारे देश दोबारा आकर उसका अनुमोदन नहीं करते। 160 देश जब बात करते हैं कोई एक देश का समझ का अंतिम फैसला नहीं होता।

The BJP and the apologist Ministers of the Prime Minister need to be reminded that in multilateral negotiations, there cannot be a perfect or country specific solution or agreement. If that argument were to be extended or taken forward, there will not be one multilateral agreement but 160 agreements of the WTO - each country will take its agreement, sign it and bring it back.

मेरी चुनौती है प्रधानमंत्री को एवं उनकी सरकार को या तो वो सामने आएं सदन में बात कर लें, वर्ना अगर वो सोचते हैं कि उनके पास कोई बेहतर समाधान है इस देश के लिए तो बाली का जो करार था उसको वो रिजेक्ट कर दें, मेरी चुनौती है इस पर ।

श्री आनन्द शर्मा ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से coma and interim की बहुत समझ की उम्मीद नहीं रखता हूं बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं। इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि या तो

उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई या उन्होंने जानबूझ कर राजनैतिक प्रेरणा से एक ऐसा बयान दिया है जो अपने आप में गलत है। यह सरकार विपक्ष के साथ एक तरफ सहयोग की बात करती है पर अपने व्यवहार में खराब करते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर पहले दिन से सरकार ने अपनी बदनीयती ना दिखाई हो। लोकसभा के अन्दर विपक्ष के नेता का दर्जा ना देना, बावजूद इसके कि कानून इस पर स्पष्ट है, बाद में स्टेटस स्पष्ट हैं। 1977 से लेकर 2003 का CVC Act 2005 का RTI Act और बहुत ऐसे फैसले हैं जो उनकी गलत नीयत और दुर्भावना को सामने लाते हैं। हमने प्रयास किया है कि संसद चले, संसद में चर्चा हो, आज भी हमने यही मांग की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आ जाएं। संसद जब चलती है तो वे संसद में नहीं बोलते, पहले कहा जाता था। भाजपा के द्वारा–मेरा सीधा प्रश्न है कि पिछले महीने से आज तक जब से संसद चली है, प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रश्न का उत्तर संसद में नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने एक भी विषय पर एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने एक भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इनकी कार्यशैली वही है जो गुजरात के सीएम के रूप में थी और हम ने चुनाव के दौरान आपको चेताया था आगाह किया था, वो विश्वास नहीं करते, संस्थाओं का सम्मान नहीं करते।

दूसरा विषय जिस पर हम सदन में चर्चा चाहते हैं। वो संस्थाओं को कमजोर करना, संस्थाओं का अपमान करना और शासन और प्रशासन में भय का वातावरण बनाना और खौफ का वातावरण बनाना जिससे सब लोग भयभीत हो जाएं।

It is very clear what I am saying because what he said is incorrect, utterly false, misleading, irresponsible and I dare him to reject it and let him stand his boastful claims and bravado that for him to take a stand or what stand has he taken. There were no negotiations in Geneva. Negotiations finished in Bali. Next negotiations will be at the Ministerial Summit and they are trying to confuse everyone and I am sure some of those who speak good English and understand good English between innocuous comas, many of you would have been told that some of the learned people, please go and read what is written. Those who understand the meaning of the word interim and permanent solution and in the interim until negotiations permanent solution is reached, no Member country will challenge another Member country in the WTO. Interim is always linked to a tangible future and that is the outcome of Bali.

It is a systematic subversion of institutions, degradation of institutions, disregard of constitutional provisions and creating an atmosphere of suspicion, distrust and fear in administration and governance of the country. That is happening and what is visible.

On the question of WTO and use of coma and or, Shri Sharma said my understanding of English language is very clear. This was after 7 days of negotiations which went

through the night and I think my understanding of English language is very clear and I do not need to relearn English language from Shri Narendra Modi or Mr. Arun Jaitley. My teachers were very good in English. So this is to confuse you people, nothing else. Shri Sharma further said I can teach the difference in 'coma' and 'or'. You have to go by my plenary statement at WTO, You have to go by my statement - main statement - made on the 18th of Dec. Please take it out. It is crystal clear and I stand by every word of that statement. Now this is to confuse. My question is what have they got. You have the complete protection and had blown it away. They are behaving so arrogantly in a multilateral organization for what. Since 1995 nothing was done, they also had Commerce Ministers from Mr. Maran to Mr. Arun Jaitley. Please read the Cancun - what Arun Jatilay signed on. So for Modi to say that we surrendered, on the contrary we fought tenaciously, we forced the issue. We had a situation where the US and EU were joined by China who broke ranks with us in G-33 proposal. Yet we put together a grand global coalition and that coalition was majority of the countries and we forced the issue and that is why this solution.

On the question of the competence of Mr. Maran, Shri Sharma said this issue was never forced on their agenda I respect Mr. Maran. The Doha development agenda which is presently under discussion - Mr. Maran made a notable contribution. What I am saying is that issue since the Uruguay round on Agriculture was signed in 1994 and am not making it a partisan issue. Until Dec 2013 was never put on the agenda until India forced it. That is all. It is not the BJP or the NDA which forced on the agenda. It was we, the UPA and India which forced it on them. It is a matter of fact and record. Mr. Modi may rewrite the history of India but he cannot rewrite the facts and record in Geneva.

On the question of Trade Facilitation agreement, Shri Sharma said India has interest in the Trade facilitation Agreement and India was one of the proponents. Let this government say we reject TFA because we have 4.3% share in services sector and close to 2% - 1.8% in merchandise trade, both put together India's share in trade is 1 trillion+. Most of the things of the Trade Facilitation Indian has already been done including electronically linking, your terminals ports for imports and exports, electronic data into changeability, e-filing of applications, electronic bank realization certificates which we have created gate through RBI, is it in India's interest or not which brings down the transaction cost. The Minister had made the statement that India is not isolated in response to question made by one of the senior parliamentarian in Rajya Sabha Shri Sita Ram Yechury who said that I have no objection but you are left in the company of three countries and said we have a majority of countries but they could not speak and they wanted to speak through India that is a insult to those countries.

To another question on National Judicial Appointment Bill and whether the Congress party is supporting this Bill and the Bharat Ratna Awards, Shri Sharma said first of all I would not make any comment on what is being speculated on the Bharat Ratna which is the highest national honour. It is for the government of the day to take that call and share their decision with the country. We would appreciate if the government stops functioning through programmed leaks that makes an upfront statement or the thinking.

Shri Sharma also said when they were in government, they opposed everything and everything had to be stalled, sent to Standing Committee, parliament did not function. Now today some legislative work is being done, parliament is functioning; suddenly they say good days have come. It is all because of us that the parliament is functioning and there has been discussion in the parliament. They want to have credit for both the periods.

Secondly, Shri Sharma said it was the UPA who brought National Judicial Appointment Bill and constitutional amendment Bill. It is a sensitive issue. The Constitutional Amendment Bill was passed during UPA regime. Do you want that we should also stall the proceedings and disrupt the functioning of the parliament. There is a voting on the Constitutional Amendment Bill. It is for this reason that that cannot be challenged. The Standing Committee had submitted their recommendation on the same. Today only they said they will bring a new one. It is the right of the political parties to have a look and study the new one. Being a responsible opposition, we are talking with the government. We want to see the architecture of the new Bill which they want to bring after withdrawing the present.

To another question on the statement of Mohan Bhagwat of RSS, Shri Sharma said this country has always been multi-cultural, multi-lingual, multi-religious and diverse. That is the beauty and the strength of India and should be retained as such. We are much disturbed and concerned sometime as in recent weeks when statements are being made.

(Tom Vadakkan)
Secretary
Communication Deptt.